

दिनांक: 13.08.2026

समय: 18.30 पीएम

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर-राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट को भी मंजूरी।

पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में वृक्ष संरक्षण विधेयक-2026 लाने का निर्णय-खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया।

प्रदेश के 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में युवा स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद कर उनके काम की सराहना की।

000

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। इनमें यूसीसी ड्राफ्ट, राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाले ट्री प्रोटेक्शन बिल-2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों में रियायत और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के भूमि आवंटन नियमों में भी बदलाव संबंधी निर्णय लिये गये। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। श्री पटेल ने बताया कि राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 यानी यूसीसी का मसौदा मंजूर कर दिया गया है। श्री पटेल ने कहा कि इस प्रस्तावित मसौदे के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव इन संबंधी मामलों में पूरे राज्य में एक समान कानून लागू किये जाएंगे। हालांकि आदिवासी समुदाय के पारम्परिक रीति रिवाजों और संस्कृति की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

-----

राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष संरक्षण विधेयक-2026 लाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत खेजड़ी, रोहिड़ा और पीपल सहित कुल 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। श्री पटेल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य रेगिस्तान के विस्तार को रोकना और हरित आवरण बढ़ाना है।

-----

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवा नियम 1951 में संशोधन किया गया है। मृत सरकारी कर्मचारियों की पुत्रवधु को भी अब अनुकम्पा नियुक्ति का फायदा मिल सकेगा। सेरोगेट माताओं को नब्बे दिन का मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सभी सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुभव की शर्त में दो साल की छूट मिल सकेगी। वहीं एकल महिलाओं को मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव अब 3 की बजाए 6 चरणों में दी जाएगी।

-----

पीएचईडी मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के निर्णय को लेकर ग्राम जल स्वच्छता कमेटी बनायी गयी थी। इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इससे संबंधित प्रावधानों का भी बैठक में अनुमोदन किया गया।

000

राज्य के 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली गई। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई इस लॉटरी प्रक्रिया के साथ ही आगामी

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। जयपुर स्थित मुख्यालय में स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा की मौजूदगी में ये लॉटरी निकाली गई। इसके अनुसार 309 शहरी निकायों में 50 पद अनुसूचित जाति, 11 जनजाति और 60 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किये गये हैं। 188 निकायों के प्रमुख पद अनारक्षित रखे गये हैं। अनारक्षित पदों पर किसी भी वर्ग के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुला रहेगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगमों में महापौर का पद अनारक्षित रखा गया है। वहीं कोटा नगर निगम का मेयर पद ओबीसी महिला के लिए रिजर्व किया गया। अजमेर और भरतपुर में महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया है। वहीं नये बने नगर निगम भीलवाड़ा, अलवर और पाली में भी महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया है। मीडिया से बातचीत में स्वायत्त शासन मंत्री श्री खर्रा ने बताया कि समय की कमी के बाद भी इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया गया है।

प्रमुख शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि इस बार आरक्षण तय करने में पारदर्शी प्रक्रिया और रोटेशन फार्मूले के विशेष ध्यान रखा गया है।

निकाय प्रमुखों के आरक्षण के बाद अब 17 अगस्त को वॉर्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। जिलों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वॉर्डों का आरक्षण कलेक्टर के स्तर किया जाएगा।

000

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सौ से अधिक कलाकारों को केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किये। नई दिल्ली में हुए इस समारोह में वर्ष 2024-25 के लिए ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच और अन्य कला रूपों के लिए दिये गये। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार कलाकारों की प्रतिभा और समर्पण को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

000

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जयपुर में युवा स्टार्टअप और उद्यमियों के साथ संवाद किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में श्रीमती सीतारमण ने राजस्थान के स्टार्टअप ईको सिस्टम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां के स्टार्टअप फाउंडर्स और युवा उद्यमियों को वित्तीय समावेशन और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था के बारे में पूरे देश के समक्ष बात करने का अवसर मिलना चाहिए।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल क्रांति के महत्व पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहे।

000

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच करवाई जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही इस पहल से लगभग 75 हजार जरूरतमंद विद्यार्थियों को चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर ने बताया कि बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याओं का शुरुआती स्तर पर इलाज बहुत जरूरी है। कमजोर दृष्टि के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इसी सोच के साथ आंखों की जांच और निःशुल्क चश्मा वितरण की ये मुहिम शुरू की जा रही है।

000